Tirupati Balaji Group / Established 2009 / Ghaziabad
R.N.I No. UPBIL/2009/28691, DAVP Code: 101473

Page 8 / Price Rs. 2.00 / Ghaziabad, Sunday, 27 December 2020
Postal Registration No. UP/GBZ-80/2016-18

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-12 Issue - 30

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

News of the Week

दुनियाभर के 190 से ज्यादा देश कोरोनावायरस की चपेट में हैं। भारत में 31 दिसंबर 2020 तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। विश्व में 8.26 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में है।

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2
48 जोड़ों की शादी, बचत की सीख लेकर ससुराल...

पेज नंबर 7
Bills will free farmers from middlemen: VK...

जिले में कोरोना वैक्सिनेशन की तैयारी पूरी

70 स्थानों पर लगेगी वैक्सीन, 54 पीएचसी सीएचसी भी शामिल

गाजियाबाद : स्वास्थ्य विभाग ने जिले में कोरोना वैक्सिनेशन के लिए माइक्रो प्लान तैयार कर लिया है। जिले में प्रथम चरण के कोरोना वैक्सिनेशन के लिए 70 स्थल चिहिन्त किए है। वहीं 54 पीएचसी–सीएचसी भी शामिल किए है। जिला एमएमजी अस्पताल को मुख्य टीकाकरण स्थल बनाया गया है। यहीं पर मुख्य वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। यहां से ही सभी केंद्रों पर वैक्सीन भेजी जाएगी। टीकाकरण स्थलों पर लोगों की भीड़ ज्यादा न हो इसके लिए लोगों को दो से तीन अलग–अलग समय में विभाजित कर बुलाया जाएगा। दूसरे वैक्सिनेशन में टीकाकरण स्थल को बढ़ाया जाएगा। पहले चरण में डाक्टर और मेडिकल कर्मियों को ही टीके लगाए जाएंगे।

वैक्सीन के रखरखाव का रखें विशेष ध्यान : नोडल अधिकारी

गाजियाबाद : जनपद के नोडल अधिकारी सेंथिल पांडियन सी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों के संबंध में बैठक की। जिसमें उन्होंने कोविड की रोकथाम व वैक्सीन के उपलब्ध होने के बाद उसे रखे जाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी की। नोडल अधिकारी ने वैक्सीन के रखरखाव में विशेष ध्यान रखने और इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में ही कोविड–19 कंट्रोल रूम की स्थापना कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद जिला अस्पताल में जिला वैक्सीन स्टोर एवं कोल्ड चेन का निरीक्षण किया।

कोरोना से एहतियात के साथ नए साल का स्वागत

गाजियाबाद : नए साल 2021 के स्वागत को लेकर शहर भर में कोरोना से एहतियात के साथ जश्न मनाया गया। हालांकि इस साल पहले की तरह तो ज्यादा कार्यक्रम नहीं हुए। कुछ दुकान और रेस्टोरेंट लाइटों फूलों व गुब्बारों से सजाये गयें। इस साल ज्यादातर सोसायटियों में कोरोना को देखते हुए सामूहिक रूप से कार्यक्रम नहीं हुए। लोगों ने अपने घर पर परिवारजनों के साथ ही नया साल मनाया। वसुंधरा निवासी सतेंद्र ने बताया कि उन्होंने इस साल कोरोना संक्रमण को देखते घर पर परिवारजनों के साथ नया साल मनाया और कोरोना से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की। शहर भर के धार्मिक स्थलों, माल–मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट में कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन किया गया। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद प्रवेश दिया जाएगा।

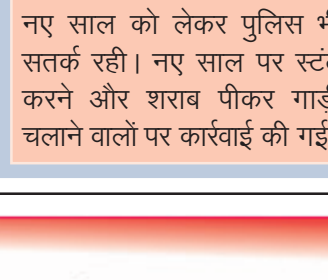

पुलिस तैनात रही

नए साल को लेकर पुलिस भी सतर्क रही। नए साल पर स्टंट करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई।

Fire at Maruti showroom Meerut Road, 26 cars damaged

GHAZIABAD: A massive fire broke out at a car showroom at 10am near Delhi Public School on Meerut Road on Sunday, police said. The cops added that there were no injuries in the incident. The fire department took over an hour to control the situation, but four cars were completely burnt. The fire department suspect short circuit to be the reason behind the blaze. Chief fire officer (CFO) Sunil Kumar Singh said three fire tenders from several areas were initially sent to the Maruti Suzuki showrrom. "It took a total of 10 fire tenders an hour to douse the flame," he said The firemen said four cars — parked in the car showroom — were completely destroyed. Twenty-six cars were damaged, an official said, adding that the firm suffered a loss of over Rs 1 crore. "We have saved 150 cars in the showroom. At the time of the incident, some employees were inside the showroom," he added. An employee said the fire broke out at the second floor. "Documents kept on the second floor have been damaged," he added.

कोरोना संक्रमितों को बचाने के लिए प्लाज्मा कर रहे दान

साहिबाबाद : कोरोना संकट से जूझने के बाद अवनीश झा अन्य कोरोना संक्रमित को वैश्विक महामारी से लडने के लिए प्लाज्मा दान कर रहे हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी कोरोना संक्रमित लोगों को प्लाज्मा दान करने की अपील की है। जिससे सभी घर आंगन खुशियों से गुलजार रहें। एंजल मरकरी सोसायटी में रहने वाले अवनीश झा बताते हैं कि अगस्त माह में उनका पूरा परिवार कोरोना संक्रमित हो गया था। कोरोना को हराने के बाद उन्होंने अन्य कोरोना संक्रमित को इस वैश्विक महामारी से निजातदिलाने का निर्णय लिया। तभी से वह लगातार लोगों के लिए प्लाज्मा दान करते आ रहे हैं। उन्होंने 120 दिन में छह बार प्लाज्मा दान किया। वह बताते हैं कि प्लाज्मा देने के लिए परीक्षण और उसे दान करना सुरक्षित है। एंटी बाडीज उपस्थित होने तक हर 15 दिनों के बाद एक दाता प्लाज्मा दान कर सकता है। प्लाज्मा दान करने से कोई नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता है। उन्होंने लोगों से प्लाज्मा दान करने की अपील की है।

चार जनवरी तक भरे जाएंगे बैक परीक्षा फार्म

गाजियाबाद : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से स्नातक, परास्नातक विभिन्न पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जून–2020 परीक्षा में बैक लगी है। वे बैक परीक्षाएं देने के लिए चार जनवरी तक आनलाइन फार्म भर सकते हैं। सीसीएसयू से संबद्ध महाविद्यालयों में संचालित स्नातक, परास्नातक व व्यवसायिक सेमेस्टर पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थी जिनकी एक परीक्षा छूट गई या फिर बैक लगी है। विवि द्वारा सेमेस्टर पूरा कराने के लिए अभ्यर्थियों को बैक परीक्षाएं कराने का मौका दिया गया है। चार जनवरी तक आनलाइन बैक परीक्षा फार्म भरे जाएंगे।

सीसीएसयू की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने वालों के परिणाम घोषित

गाजियाबाद : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से विभिन्न पाठ्यक्रम में जून–2020 में परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। श्रेणियों के आधार पर दंड और अभ्यर्थियों की सूची विवि की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सीसीएसयू से संबद्ध महाविद्यालयों से व्यवसायिक पाठ्यक्रम व पीजी सेमेस्टर परीक्षा देने वाले छात्र–छात्राओं के लिए श्रेणी के आधार पर दंड निर्धारित किया गया है। प्रथम श्रेणी में चेतावनी दी जाएगी कि इस संबंध में सावधान रहें। दूसरी श्रेणी में संबंधित विषय कोड की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। तीसरी श्रेणी में सभी सेमेस्टर जून–2020 की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। चौथी श्रेणी में सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। साथ ही भविष्य में अगले सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। पांचवीं श्रेणी में सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। साथ ही भविष्य में दो सेमेस्टर की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। छठी श्रेणी में सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। भविष्य में तीन सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। वहीं बीएड और बीपीएड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले छात्रों के लिए भी श्रेणीबद्ध तरीके से दंड निर्धारित किया गया है। प्रथम श्रेणी में चेतावनी दी जाएगी कि इस संबंध में सावधान रहें। दूसरी श्रेणी में संबंधित विषय कोड की परीक्षा निरस्त कर दी गई है।

बढ़ रहा प्रदूषण, लोग हो रहे परेशान

साहिबाबाद : हल्की बूंदाबांदी और हवा में आयी तेजी का प्रदूषण पर असर पड़ा है। सोमवार को गाजियाबाद शहर का एक्यूआई रेड जोन से ओरेंज जोन में पहुंच गया। रविवार रात को हुई बूंदाबांदी के बाद से ठंड का प्रकोप बढ़ गया। वहीं तेज हवा की रफतार में तेजी महसूस की गई। सोमवार सुबह तेज धूम के साथ सूरज निकला लेकिन हवा की रफतार अधिक होने के कारण धूप से अधिक ठंड महसूस हुई। सोमवार को हवा की रफतार में आई तेजी से जिले के प्रदूषण में कमी देखने को मिली। पांच दिन से लगातार रेड जोन में रहा गाजियाबाद सोमवार को ओरेंज जोन में पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 233 दर्ज किया।

48 जोड़ों की शादी, बचत की सीख लेकर ससुराल गईं दुल्हन

गाजियाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत बुधवार को जनपद मेंअलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर 48 जोड़ों की शादी करवाई गई। जिनमें पहली बार प्रत्येक दुल्हन को मिशन शक्ति के तहत सिलेंडरनुमा गुल्लक भी उपहार में देते हुए उनको घर चलाने के लिए बचत की सीख अधिकारियोंऔर जन प्रतिनिधियों ने दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दो लाख रुपये सालाना से कम आय वाले परिवार की बेटी का विवाह इस योजना के तहत कराया जाता है। प्रत्येक जोड़े के विवाह पर 51 हजार रुपये खर्च किए जाते हैं। 51 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये खादी के बाद वधू के बैंकखाते में भेजे जाते हैं। 10 हजार रुपये का सामान खरीदकर शादी के वक्त दिया जाता है। छह हजार रुपये एक जोड़े की शादी की व्यवस्था जैसे कि टेंट और खान–पान में खर्च किए जाते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय व्यास ने बताया कि रजापुर ब्लॉक, भोजपुर ब्लॉक, मुरादनगर ब्लॉक और नगर निगम क्षेत्र स्थित चौधरी भवन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। चौधरी भवन में 13, मुरादनगर में आठ, भोजपुर में चार और रजापुर में 23 जोड़ों का विवाह करवाया गया है। कार्यक्रम स्थल पर कोरोना से बचाव के लिए सभी को मास्क पहनकर आने की ही अनुमति दी गई , सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने पहल करते हुए प्रत्येक दुल्हन को उपहार में सिलेंडरनुमा गुल्लक उपहार में देने की व्यवस्था की। यह उपहार भी विवाह में आकर्षण का केंद्र बना रहा। चौधरी भवन में महापौर आशा शर्मा, खोड़ा नगर पालिका की चेयरमैन रीना भाटी और रजापुर ब्लॉक में विधायक अजितपाल चौधरी और विधायक डॉ. मंजू शिवाच ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया।

बिजली निगम के प्रबंध निदेशक से की भ्रष्टाचार की शिकायत

लोनी : सामाजिक संस्था इति भ्रष्टाचार के पदाधिकारियों ने सोमवार को मेरठ स्थित बिजली निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर लोनी बिजली निगम में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत की। उन्होंने बताया कि लोनी में कमर्शियल कनेक्शन देने के लिए निगम के संविदा कर्मी स्थानीय लोगों से अवैध रूप से पैसे की उगाही करते है। इनका विरोध करने पर संविदा कर्मी लोगों के घर चेकिंग कराकर फर्जी मुकदमे लगवाने का कार्य भी करते है। उन्होंने बताया कि लोनी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पदाधिकारियों ने प्रबंध निदेशक से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

सात साल बाद भी नहीं मिला पजेशन, बिल्डर पर एफआईआर

गाजियाबाद : फ्लैट बुक करने के सात साल बाद भी पजेशन नहीं दिया गया। मामला कविनगर थानाक्षेत्र स्थित एनएच–9 के किनारे आवासीय सोसायटी बना रहे बिल्डर का है। पीडिघ्त की शिकायत के बाद एसएसपी के आदेश पर बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आईपी एक्सटेंशन, दिल्ली में रहने वाले अमित जैन ने बताया कि वर्ष 2013 में उन्होंने एनएच–9 के किनारे आवासीय सोसायटी बना रहे बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कराया था। उनके मुताबिक फ्लैट बुकिंग के समय बताया गया था कि प्रोजेक्ट में विदेशी निवेश है। लंदन की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। झांसे में आकर अमित जैन ने उक्त प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक किया और 23 लाख रुपये बिल्डर को दे दिए। फ्लैट के पजेशन के लिए जनवरी 2016 का समय दिया गया था लेकिन अभी तक पजेशन नहीं दिया गया है। पड़ताल करने पर जानकारी मिली कि प्रोजेक्ट में किसी कंपनी का विदेशी निवेश नहीं है। उनकी तरह की अन्य लोगों को झांसा देकर आरोपित बिल्डर करीब 150 करोड़ रुपये ले चुका है। इसके अलावा एक अन्य फाइनेंस कंपनी से भी बिल्डर ने प्रोजेक्ट के नाम पर 135 करोड़ रुपये का लोन ले रखा है। एसएचओ कविनगर अजय सिंह ने बताया कि बिल्डर फर्म के निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

अदालत ने सुनाई 5 वर्ष पांच माह कैद की सजा

गाजियाबाद : गिरोह बनाकर अपराध करने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश त्रिपाठी की अदालत ने एक दोषी को पांच वर्ष पांच माह कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामला मसूरी थानाक्षेत्र का है। अधिवक्ता ने बताया कि इकबाल ने अदालत में जुर्म कबूला था। इसके बाद अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत सोमवार को इकबाल को उपरोक्त सजा सुनाई। बता दें कि मसूरी थाना पुलिस ने 30 जून 2015 को इकबाल, इमरान, परवेज व हासिम को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि यह लोग गिरोह बनाकर क्षेत्र में अवैध हथियारों के बल पर बच्चों का अपहरण कर फिरौती वसूलते हैं। समाज में इनका भय है। इनके खुलेआम रहने से क्षेत्र में शांति व्यवस्था व लोक व्यवस्था भंग होने का खतरा है।

तीन शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित

साहिबाबाद : मिशन शिक्षण संवाद टीम वाराणसी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी द्वारा रविवार को आयोजित राज्य स्तरीय शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला में जनपद की तीन शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। मिशन शिक्षण संवाद टीम वाराणसी द्वारा कोरोना महामारी के बाद प्रदेश भर में परिषदीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला में प्रदेश के दो सौ शिक्षकों ने भाग लेते हुए अपने जनपदों के उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया साथ ही वाराणसी के मॉडल स्कूलों का निरीक्षण किया। कार्यशाला में गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व करते हुए नीरव शर्मा, अनुपमा तंवर और कविता वर्मा ने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए किए गए प्रयोगों, विशेष प्रयासों, ई पाठशाला का संचालन समेत अन्य उत्कृष्ट कार्यों का प्रेजेंटेशन किया। रविवार को केबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रवींद्र जयसवाल ने तीनों शिक्षिकाओं को उत्कृष्ट कार्यों को करने के लिए सम्मानित किया।

पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से की वार्ता, सुरक्षा व सुविधाएं मुहैया कराने का दिया आश्वासन

साहिबाबाद : पुलिस ने सोमवार को यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में घुसे डेढ़ दर्जन संदिग्धों को दबोच लिया। उन पर शांति भंग की कार्रवाई की गई। वहीं, किसान भी अराजकतत्वों की पहचान करने में जुटे रहे। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं से वार्ता कर सुरक्षा व सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में अराजकतत्व घूम रहे हैं। वह माहौल खराब करने की जुगत में रहते हैं। उन पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी नजर रख रहे हैं। उन्हें पकड़कर कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को यहां घुसे डेढ़ दर्जन संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा। उनसे पूछताछ की, तो पता चला कि वह किसान नहीं हैं। सिर्फ यहां घूम रहे हैं। पुलिस ने उन पर शांति भंग में कार्रवाई की। सोमवार दोपहर में एक संदिग्ध युवक को किसानों ने पकड़ा।

उससे पूछा, तो पता चला कि वह मजदूरी करता है। खोड़ा में रहता है। किसानों ने उसे आंदोलन से बाहर का रास्ता दिखाया। किसान नेताओं ने भी अपने वालंटियरों से अराजकतत्वों पर नजर रखने को कहा है। आंदोलन स्थल पर चोर–उचक्के भी सक्रिय हैं। नगर निगम द्वारा रखी गईं पानी की टंकी की टोटियां, मोबाइल व बिस्तर तक गायब हो चुके हैं। इसको लेकर पुलिस व किसान दोनों सतर्क हुए हैं। पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आंदोलन पर कड़ी सुरक्षा–व्यवस्था है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अपर जिलाधिकारी नगर शैलेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह ने सोमवार को कई बार किसान नेताओं से वार्ता की। उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। पानी, बिजली व शौचालय की व्यवस्था की जानकारी ली।

खतरा : यूपी गेट पर किसानों में बुखार, खांसी व जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी

साहिबाबाद : कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट दिल्ली बार्डर पर बुखार, खांसी व जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ी है। निजी व सामाजिक संस्थाएं इनके इलाज में जुटे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे जांच के आदेश के बावजूद आरंभ नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता नहीं बरती तो बढ़ती भीड़ में कोरोना बम फूट सकता है। वहीं, सरकारी एंबुलेंस आंदोलन स्थल से दूर खड़ी होकर बैरंग लौट रहीं हैं। कोरोना का संक्रमण अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे रोकने के लिए शासन–प्रशासन की ओर से लगातार प्रचार किया जा रहा है। यहां यूपी बार्डर पर किसान आंदोलन 28 नवंबर से जारी है, जिसमें अब किसानों की संख्या दिनोंदिन बढने लगी है। वहीं, किसान कोरोना संक्रमण से अंजान हैं और उनके चेहरों से मास्क गायब है। धरनारत किसानों के इलाज के लिए सामाजिक संस्थाओं व निजी चिकित्सकों ने शिविर लगा रहे हैं। डीएम अजय शंकर पांडेय ने स्वास्थ्य विभाग को 24 घंटे कोरोना जांच के निर्देश दिए थे। आलम यह है कि यहां निजी एंबुलेंस व चिकित्सकों की टीम जो आंदोलन स्थल पर सेवाएं दे रही हैं। वहीं, सरकारी स्वास्थ्य विभाग से भेजी गई एंबुलेंस आंदोलन स्थल से दूर खड़ी रहकर लौट रही है।

सरकार व किसानों में बातचीत के बाद 2 मुद्दों पर रजामंदी

नई दिल्ली : बुधवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों व सरकार के बीच दो मुददों पर रजामंदी हो गई। इस बार अलग ये हुआ कि सरकार के दो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल किसानों के लंगर में शामिल हो गए। तीन घंटे बाद बैठक खत्म हुई और दो मुद्दों पर रजामंदी बन गई। अगली बैठक 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे से होगी। बुधवार को लंच के दौरान तब बात बनने के आसार दिखे थे, जब किसानों के साथ मंत्रियों ने खाना खाया था। किसान लंगर में बनी दाल–रोटी अपने साथ लाए थे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उनके साथ खाना खाया। उनके साथ चाय पर भी बातचीत की। किसानों के 4 बड़े मुद्दे हैं। पहला– सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। दूसरा– सरकार यह लीगल गारंटी दे कि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी जारी रखेगी। तीसरा– बिजली बिल वापस लिया जाएगा। चौथा– पराली जलाने पर सजा का प्रावधान वापस लिया जाए। पांच घंटे की बातचीत के बाद बिजली बिल और पराली से जुड़े दो मुद्दों पर सहमति बन गई। सरकार किसानों की चिंताओं को दूर करने पर राजी हो गई। इसके बाद किसान नेताओं ने भी नरमी दिखाई। उन्होंने 31 दिसंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया। कृषि कानून और एमएसपी पर अभी भी मतभेद बरकरार हैं।

किसानों को भरोसा

पर्यावरण से जुड़े ऑर्डिनेंस में पराली के मामले में किसानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार और किसानों में इस मुद्दे पर रजामंदी बनी है। दूसरा मुद्दा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का है, जो अभी आया नहीं है। किसानों को लगता है कि इस एक्ट से उन्हें नुकसान होगा। किसानों को सिंचाई के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, वैसी ही चलनी चाहिए। इस भी रजामंदी हो गई है।

मना रही सरकार

तोमर ने बताया, 'किसान यूनियन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात करती रही। हमने अपने तर्कों से उन्हें यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहां है? जहां कठिनाई है, वहां सरकार खुले मन से विचार को तैयार है।

कृषि कानून वापस न होने तक जारी रहेगा किसान आंदोलन : नरेश टिकैत

गाजियाबाद : भारतीय किसान यूनियन (भाकियू)के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि किसान नए कृषि कानूनों को वापस कराकर ही घर लौटेंगे। सरकार की नीयत में खोट है तभी मुद्दों पर बात नहीं कर रही है। आगामी 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य साधनों से तमाम बाधाओं को पार करते हुए दिल्ली के लिए कूच करेंगे। यूपी गेट किसान आंदोलन स्थल के मंच से बोलते हुए भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। किसान इन कानूनों को मान नहीं रहा तो उस पर इन्हें थोपने की जरूरत क्या है। किसान संगठन इन कानूनों के विरोध में एकजुट हैं और किसान घरों से ठानकर आया

है कि वह इन्हें वापस कराकर ही लौटेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक होती तो मामला यहां तक न पहुंचता। वार्ता के दौरान एक या दो बार में हल निकल जाता। किसानों का यह अनिश्चितकालीन आंदोलन दिल्ली के हर बार्डर पर जारी रहेगा। कृषि कानून वापस न होने पर गणतंत्र दिवस पर किसान हर बार्डर से ट्रैक्टर–ट्राली व अन्य साधनों के अलावा पैदल ही दिल्ली के लिए कूच करेंगे।

नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश, रुकवाया

गाजियाबाद : सोमवार को सिहानी में खसरा नंबर 160 व 161 पर 0.3285 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा होने की शिकायत नगर निगम को मिली। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा रुकवाया गया है। इस दौरान अधिकारियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। जेसीबी के सामने सड़क पर बैठकर कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की गई। नगर निगम की टीम ने विरोध करने वालों को हटाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कराया है। अपर नगर आयुक्त राज नारायण पांडेय ने बताया कि सिहानी में नगर निगम की जमीन पर राकेश कुमार वर्मा द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसे तत्काल रुकवा दिया गया है। प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल दीपक शरण ने बताया कि जमीन

को अपनी बताते हुए राकेश ने जेसीबी के सामने सड़क पर बैठकर कार्रवाई का विरोध जताया। समझा बुझाकर निगम अधिकारियों ने राकेश को हटाया। राकेश व अन्य तीन व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है।

जीडीए ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण

गाजियाबाद : जीडीए ने ध्वस्तीकरण अभियान तेज कर दिया है। सोमवार को प्रवर्तन जोन–7 में अवैध रूप से किए गए निर्माण सचल दस्ते ने ध्वस्त कर दिया। जीडीए अपर सचिव सीपी त्रिपाठी की देखरेख में सहायक अभियंता रणबीर सिंह ने यह कार्रवाई की है। सहायक अभियंता आरबी सिंह ने बताया कि शालीमार गार्डन के बी–44 में काफी दिनों से अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। प्रवर्तन खंड द्वारा नोटिस जारी करके निर्माण बंद करने को कहा गया लेकिन कार्य बंद नहीं किया गया। ध्वस्तीकरण आदेश पारित कराने के बाद सोमवार को पूरा निर्माण तोड़ दिया गया है। शालीमार गार्डन क्षेत्र में आधा दर्जन अन्य अवैध निर्माणों को भी चिह्नित कर लिया गया है। उधर जीडीए सचिव द्वारा डीएम और एसएसपी को पत्र

भेजकर अवैध निर्माणों को तोडने के लिए फोर्स की मांग की गई। पत्र में लिखा है कि राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में कई अवैध कालोनी विकसित की जा रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा की गई समीक्षा के दौरान अवैध निर्माणों पर सख्ती के निर्देश दिए गए थे।

1010 अधिवक्ताओं ने घर के लिए जताई इच्छा

गाजियाबाद : शहर में घर बनान की 1010 अधिवक्ताओं ने आवेदन किया है। जल्द ही आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की सूची जीडीए उपाध्यक्ष को सौंपी जाएगी, ताकि फ्लैट व प्लाट आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। सोमवार को यह बातें गाजियाबाद बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुनीष त्यागी ने कहीं। मालूम हो, कि गाजियाबाद कचहरी में वकालत करने वाले कई अधिवक्ताओं के पास शहर में घर नहीं हैं। उन्हें दूर–दराज के इलाकों से रोजाना वकालत करने के लिए राजनगर स्थित कचहरी में आना पड़ता है। ऐसे अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं को परेशानी से निजात दिलाने के लिए यह सारी कवायद की जा रही है।

EDITORIAL

Easing off: On coronavirus situation in India

As 2020 draws to a close, Indians will look forward to the new year with wariness and hope after suffering one of the worst years in history, health-wise (nearly 1,48,000 registered deaths due to COVID-19) and economically (loss of livelihoods). The pandemic continues to rage — daily infections and deaths are scaling fresh peaks in Europe, the U.S. is closing in on 20 million confirmed cases and 3.4 lakh deaths and in some countries in Latin America, cases have remained high and are rising. In contrast, while India still registers the highest number of daily infections and deaths in Asia, the daily rate has come down significantly to a seven day rolling average of less than 24,000 cases and 250 deaths between December 20-26, from the peak of close to a lakh and more than a 1,000 deaths a day in mid-September. These are much lower numbers compared to the U.S. and comparably fewer than those registered in the larger countries in Europe and Latin America. India still tests a middling number: 732 tests and 15.8 confirmed cases per million people, compared to the rest of the world. The testing numbers have fallen slightly in the past month, but the significant drop in recorded deaths suggests that, rather than experiencing a new peak in daily infections and deaths, India still remains in the "down phase" since the September peak. That the case and death curves are headed further south is a good sign for the health infrastructure.

While no other country barring the U.S. has reached or crossed the per day peak of nearly one lakh cases that India registered in September, the lower number of cases registered recently even as the country eased its physical distancing measures and travel restrictions and went through a festive season might come as a surprise. But as virologists Jacob John and M.S. Seshadri have argued, the peaking in September denoted the pandemic's widespread nature in urban and semi-urban areas and was reflected even more apparently in the ICMR's serosurveys. These serosurveys revealed a much higher number of undetected infections, many of them asymptomatic, before the September peak. As the virus ravaged the urban centres and spread to rural areas, the virologists estimated that nearly a third of the population had already been exposed, indicating that half of the "herd immunity" level required to end the spread had already been reached by mid-September. This explains why daily case and fatality rates stay low and also suggests that after India begins its vaccination drive, the epidemic should ease further and could become endemic. This does not lessen the dangers of local outbreaks and the complications of the spread of new variants from abroad. The standard safety measures — mask wearing, hand hygiene, absence of crowding and renewed testing and tracing — must remain.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

Farmers block Delhi-Meerut Expressway again, give government 10 days on laws

GHAZIABAD/RUDRAPUR: Members of the Bharatiya Kisan Union (BKU), who have been protesting at UP Gate for nearly a month, blocked the whole of Delhi-Meerut Expressway (DME) for five hours from 11am on Saturday. The farmers gave a 10-day ultimatum to the Centre and threatened massive protest if the stalemate on the three agriculture laws continued. As a section of farmers blocked the expressway, many others joined the protesters from different districts of the state later in the day. In Udham Singh Nagar in Uttarakhand, 1,500 farmers were booked for allegedly clashing with police on their way to UP Gate to join the agitation. BKU leader Rakesh Tikait, who has been leading the protest at UP Gate, on Saturday led a group of farmers from Rampur in 100 tractor trolleys. "We have been receiving numerous complaints about the police stopping other

farmers from reaching the protest site. I went to Rampur myself and brought farmers to the protest site," said Tikait. "We have also given 10 days to the Centre to come up with something concrete on the farm laws. If the government fails to do so, we will intensify our protest and gherao the houses of BJP MPs one by one," he added. According to a rough estimate, more than 3,000 farmers are camping at UP Gate currently, but their numbers are expected to swell with many more joining the movement from other areas. Through Saturday, the police remained on high alert, anticipating chaos. "In view of the heightened activities at UP Gate, we have revisited our strategy to maintain law and order. The area has been divided into seven zones and 13 sectors. Senior police officers and the district magistrate himself have been camping at the site," an official said. "On Saturday, we had to divert traffic at UP Gate as farmers had blocked the DME for about five hours from 11am. Commuters were stuck in snarls at various places," he added. Meanwhile, a complaint was lodged at Kaushambi police station on Saturday after death threats were allegedly issued to Tikait. "Our leader, Rakesh Tikait, received death threats over phone. Accordingly, we informed the police," said Shamsher Rana, the media in-charge of BKU. A police officer said, "We are taking the matter seriously and have formed a surveillance team to investigate the threats.

ड्यूटी से अनुपस्थित, फिर भी जबरन हाजिरी लगवाने का आरोप

गाजियाबाद : नगर निगम में भी घपले थमने का नाम नहीं ले रहे है। अब नगर निगम स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी राहुल कुमार ने सफाई नायकों से अवैध वसूली का आरोप लगाया है। इस संबंध में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर से शिकायत की गई है। राहुल का आरोप है कि चालक खुद को एक संगठन का अध्यक्ष बताता है और उसके दो बेटे, दो भाई और दो भतीजे भी विजयनगर जोन में कार्यरत हैं। जो कि ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन जबरदस्ती हाजिरी लगवाते हैं। आरोपी का वाहन छह माह से खराब है और गैराज पर ही खड़ा है।

डीएल, परमिट नवीनीकरण, फिटनेस व अन्य कामों की समयावधि बढ़ी

गाजियाबाद : वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते 31 दिसंबर तक दी गई रियायत फिलहाल आगे बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार से आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन मुख्यालय जारी किए गए आदेश से गाजियाबाद जिले में करीब 30 हजार लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल, वर्ष 2020 में जिन लोगों के परिवहन कार्यालय संबंधी काम मार्च से दिसंबर से बीच होने थे। उन्हें 31 दिसंबर तक काम कराने की रियायत दी गई थी। उदाहरण के रूप में किसी के डीएल की समयावधि सितंबर माह में खत्म हो रही थी तो उसे नवीनीकरण के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था लेकिन अभी भी काफी संख्या में लोगों के परिवहन कार्यालय संबंधी कामकाज नहीं हो सके थे। ऐसे में जनहित में यह समयावधि बढ़ा दी गई है। अब 31 मार्च 2021 तक की छूट दी गई है। डीएल नवीनीकररण, फिटनेस, परमिट नवीनीकरण व परिवहन कार्यालय संबंध कामकाज अब लोग 31 मार्च तक करा सकेंगे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारण विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि परिवहन मुख्यालय से मिले आदेशों के क्रम में रियायत की समयावधि बढ़ा दी गई है।

RWA body drops key members, deputy registrar seeks response

NOIDA: More than 20 founder and life members have objected to Federation of Noida Residents Welfare Association (FONRWA) doing away with their membership. They are also joined by some residents welfare associations (RWAs) questioning FONRWA's new rule of no additional social or honorary post to be held by any RWA member. After lifetime members complained to Office of Deputy Registrar Firms Societies and Chits, Meerut on December 11, a reply was sought by Meerut deputy registrar from FONRWA on December 21 on the matter. "The meeting which was organised by the FONRWA on December 6 was against the bylaw rules of the organisation when they removed the founder and life membership rules of the parent RWA body of the city," said P S Jain, the former life member of FONRWA.

दंपती के झगड़े में बीच–बचाव करने पहुंची महिला की ईंट से पीटकर हत्या

लोनी : कोतवाली क्षेत्र की मुस्तफाबाद कालोनी में रविवार शाम दंपती के झगड़े का बीच–बचाव कराने पहुंची महिला की पति ने ईंटों से पीट–पीटकर हत्या कर दी। स्वजनों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपित पति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इकराम नगर कालोनी में चांद बानो (55) परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थीं। उसी मकान में शबनम भी रहती हैं। दोनों रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करती थीं। पुलिस के मुताबिक शबनम का अपने पति नफीस से सात वर्ष पूर्व झगड़ा हो गया था। तभी से दोनों अलग–अलग रहते हैं। सोमवार शाम करीब सात बजे चांद बानो और शबनम रिश्तेदार आमिर, अमन के साथ गाजियाबाद रोड से घर जा रहे थे। मुस्तफाबाद कालोनी में नफीस अपने साथी अंसार के साथ खड़ा हुआ था। शबनम को देखकर उसने युवकों के साथ घूमने का कारण पूछा। जिसपर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। बीच–बचाव करने पहुंची चांद बानों पर नफीस ने ईंट से कई वार कर दिए। उन्हें उपचार के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

लोनी में सरेआम युवक की पीट–पीटकर हत्या

गाजियाबाद : लोनी थानाक्षेत्र में लोनी–खजूरी पुस्ता मार्ग पर हमलावरों ने फूलों की दुकान के विवाद में अजय शर्मा (35) को ऑटो से उतारने के बाद सरेआम रॉड से पीट–पीटकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सोनिया विहार दिल्ली निवासी मुख्य आरोपी गोविंद शर्मा और उसके साथी अमित को गिरफ्तार कर लिया। घटना के वक्त मौजूद भीड़ में से कोई भी अजय को बचाने नहीं आया। आरोपी ने पूर्व में ही अजय को हत्या की धमकी दी थी पर पुलिस ने कार्रवाई के बजाय लीपापोती कर दी। एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले दो एसआई व हेड कांस्टेबल धीरज चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया।

दुनियाभर में इस समय 232 कोरोना वैक्सीन पर चल रहा काम

अप्रूवल हासिल करने वाली वर्ल्ड की 9वीं वैक्सीन है कोवीशील्ड, जानिए विश्व में बन रही कोरोना वैक्सीन का स्टेटस

दुनियाभर में इस समय 232 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। डब्ल्यूएचओ वैक्सीन लैंडस्कैप के मुताबिक, इनमें भी 172 वैक्सीन प्री–क्लीनिकल ट्रायल्स में हैं। यानी इन वैक्सीन की अभी लैब्स में ही टेस्टिंग चल रही है। वहीं, 60 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। आम तौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स में कई साल लग जाते हैं। पर कोरोना को इमरजेंसी मानते हुए दुनिया में अब तक 9 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। इस समय चीन की 4, रूस की 2, अमेरिका की 2 और ब्रिटेन की एक वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवलध्अप्रूवल मिल चुका है। इनमें सबसे नई वैक्सीन ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेक की कोवीशील्ड है, जिसे ब्रिटेन ने 30 दिसंबर को इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। करीब 16 देशों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। दुनियाभर में 7 वैक्सीन अब भी फेज–3 ट्रायल्स में हैं और उन्हें कहीं भी अप्रूवल नहीं मिला है। 20 वैक्सीन फेज–2 ट्रायल्स में हैं और 22 वैक्सीन पहले फेज के ह्यूमन ट्रायल्स में है। फाइजर की वैक्सीन को कम से कम 12 देशों में अप्रूवल मिल चुका है। फाइजर ने भारत में भी इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भी अपने–अपने वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। एक्सपर्ट कमेटी ने इन कंपनियों से और जानकारी मांगी है।

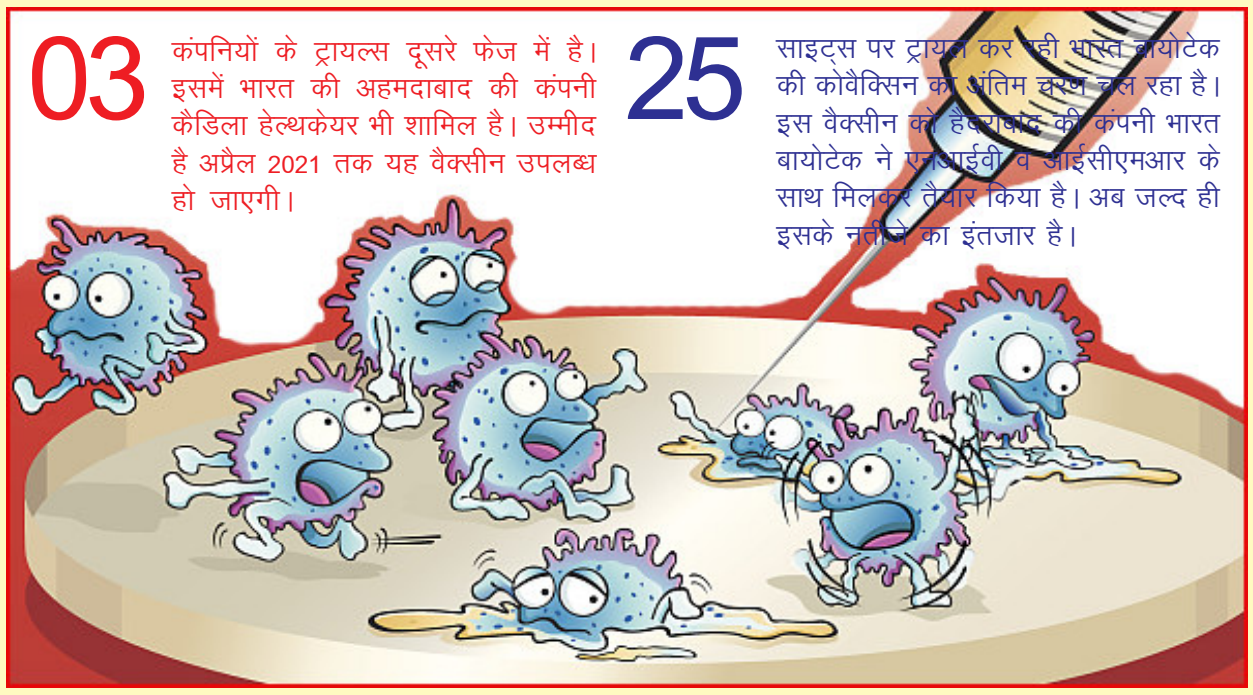

03 कंपनियों के ट्रायल्स दूसरे फेज में है। इसमें भारत की अहमदाबाद की कंपनी कैडिला हेल्थकेयर भी शामिल है। उम्मीद है अप्रैल 2021 तक यह वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी।

25 साइट्स पर ट्रायल कर रही भारत बायोटेक की कोवैक्सिन का अंतिम चरण चल रहा है। इस वैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने एनआईवी व आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार किया है। अब जल्द ही इसके नतीजे का इंतजार है।

चार वैक्सीन के नतीजे आए, चारों को मिला अप्रूवल

1. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी/एस्ट्राजेनेका

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर वैक्सीन (कोवीशील्ड) बनाई है। यह शुरुआती नतीजों में 90 प्रतिशत तक असरदार पाई गई है। दुनिया की प्रमुख वैक्सीन प्रोडक्शन कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने 7 दिसंबर को भारत में कोवीशील्ड के इमरजेंसी अप्रूवल मांगा था। इस पर भारत की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवीशील्ड से और डेटा देने को कहा है। ब्रिटेन में 30 दिसंबर को अप्रूवल मिलने के बाद भारत में भी इसे अप्रूवल मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

2. फाइजर और बायोएनटेक

अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की जॉइंट कोरोना वैक्सीन फेज–3 ट्रायल में 95 प्रतिशत असरदार साबित हुई है। न्ज्ञ में इस वैक्सीन को 2 दिसंबर को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इसके बाद अब तक 16 देशों ने इसे अप्रूवल दिया है। कई देशों में प्रायरिटी ग्रुप्स को वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

3. मॉडर्ना (अमेरिका)

अमेरिका की बॉयोटेक कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसका बनाया वैक्सीन कोरोना के मरीजों को बचाने में 94.5 प्रतिशत तक असरदार है। यह दावा लास्ट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर किया गया है। यह वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है। अमेरिका के ड्रग रेगुलेटर ने इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। इससे अमेरिका में वैक्सीनेशन के लिए दो वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। मॉडर्ना इस समय यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ में भी अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल हासिल करने के लिए कोशिश कर रही है।

4. गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट (रूस)

रूस में बनी वैक्सीन स्पूतनिक व ट्रायल के दौरान कोरोना से लड़ने में 95 प्रतिशत असरदार साबित हुई है। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे शुरुआती एनालिसिस में ये बात सामने आई है। पहला डोज देने के 28 दिन बाद इस वैक्सीन ने 91.4 प्रतिशत इफेक्टिवनेस दिखाई थी। डॉ. रेड्डी'ज लैबोरेटरी के साथ रूसी संस्था का करार हुआ है और भारत में फेज–2/3 के कम्बाइंड ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। रूस में प्रायरिटी के आधार पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है।

16 के ट्रायल्स दूसरे फेज में, 3 हमारे काम के

1. कैडिला हेल्थकेयर (भारत)

इस समय 16 कंपनियों के ट्रायल्स दूसरे फेज में है। लेकिन इनमें भी अहमदाबाद की कंपनी कैडिला हेल्थकेयर समेत 3 कंपनियां दूसरे फेज में हैं। बाकी 13 कंपनियों के वैक्सीन के फेज–1 और फेज–2 के ट्रायल्स एक साथ चल रहे हैं। कैडिला हेल्थकेयर के वैक्सीन के नतीजे जल्द ही सामने आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल–2021 तक यह वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगा।

2. शियामेन यूनिवर्सिटी (चीन)

चीन की शियामेन यूनिवर्सिटी ने हांगकांग यूनिवर्सिटी और बीजिंग की एक कंपनी के साथ मिलकर नैजल वैक्सीन बनाया है। इसके फेज–1 के नतीजे सफल रहे हैं। यह फिलहाल फेज–2 ट्रायल्स में है। यह नेजल स्प्रे की तरह होगा और इंजेक्शन लगाने की जगह सिर्फ नाक में स्प्रे करना काफी होगा।

3. क्योरवैक (जर्मनी)

जर्मन कंपनी क्योरवैक के वैक्सीन के ट्रायल्स ने भी पिछले कुछ समय में गति पकड़ी है। अब तक वैक्सीन असरदार साबित हुआ है। इस वजह से कंपनी ने अपना वैक्सीन यूरोप के सभी देशों में पहुंचाने के लिए नेटवर्क खड़ा कर लिया है।

चीन में 4, रूस में 1 वैक्सीन को ट्रायल्स से पहले ही इमरजेंसी अप्रूवल

1. सिनोवेक (चीन)

चीन की प्राइवेट कंपनी सिनोवेक के इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के फेज–1/2 ट्रायल्स के नतीजे जून में आए थे। उसके बाद कंपनी ने 743 वॉलेंटियर्स को ट्रायल्स में शामिल किया था और उनमें से किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं दिखे। नवंबर में ही इस ट्रायल्स के नतीजे घोषित हुए। ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की में अंतिम फेज के ट्रायल्स शुरू हुए। अब तक इसके नतीजे नहीं आए हैं।

2. वुहान कैंडिडेट

चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म ने वुहान इंस्टिटच्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर यह वैक्सीन बनाया है। इसके फेज–1/2 ट्रायल्स के नतीजे अच्छे आए। फेज–3 ट्रायल्स पेरू, मोरक्को और यूएई में शुरू हुए थे। सितंबर में यूएई ने सिनोफार्म के वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया।

3. बीजिंग कैंडिडेट

बीजिंग इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की ओर से विकसित वैक्सीन को चीन की सरकारी कंपनी सिनोफार्म मार्केट में उतारने की तैयारी में है। इसे भी चीन के साथ–साथ यूएई में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है।

4. कैनसिनो बायोलॉजिक्स

चीनी कंपनी कैनसिनो बायोलॉजिक्स ने चीनी मिलिट्री के रिसर्च इंस्टिट्यूशन के साथ मिलकर वैक्सीन बनाया था। इसे चीन की मिलिट्री ने 25 जून को ही एक साल के लिए मंजूरी दे दी थी। उसके बाद कंपनी ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और रूस में फेज–3 ट्रायल्स किए, लेकिन उसके नतीजों की घोषणा अब तक नहीं की है।

5. साइबेरिया का वेक्टर इंस्टिट्यूट

रूस ने 15 अक्टूबर को साइबेरिया के वेक्टर इंस्टिट्यूट के कोरोनावायरस वैक्सीन ईपीआईवेसकोरोना को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। शुरुआती स्टेज में प्लेसेबो–कंट्रोल्ड ह्यूमन ट्रायल्स में 100 वॉलेंटियर्स को यह वैक्सीन लगाई गई थी। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन से कम से कम छह महीने तक इंसान के शरीर में एंटीबॉडी रहती हैं।

भारत की स्वदेशी वैक्सीन समेत 5 वैक्सीन अंतिम दौर में

1. भारत बायोटेक का कोवैक्सिन (भारत)

भारत के लिए खास माने जा रहे स्वदेशी वैक्सीन– कोवैक्सिन का फेज–3 ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। करीब 25 साइट्स पर यह ट्रायल्स हो रहे हैं। इस वैक्सीन को हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने नेशनल इंस्टिटच्यूट ऑफ वायरलॉजी (एनआईवी) और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ मिलकर तैयार किया है। अब तक के ट्रायल्स में वैक्सीन प्रभावी रहा है, अब फेज–3 ट्रायल्स के नतीजों का इंतजार है।

2. जैनसेन फार्मा (अमेरिका)

अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सब्सिडियरी जैनसेन फार्मा का इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फेज–1/2 ट्रायल्स में असरदार साबित हुआ है। 60 हजार लोगों पर इसका अंतिम फेज का ट्रायल्स चल रहा है।

3. मेडिकार्गो (कनाडा)

कनाडा के ड्रग डेवलपर मेडिकार्गो ने भी फेज–2/3 कम्बाइंड ट्रायल्स शुरू किए हैं। शुरुआती स्टेज में कंपनी के वैक्सीन और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) के वैक्सीन बूस्टर ने वायरस को खत्म करने वाले एंटीबॉडी बनाने में कामयाबी हासिल की है। मेडिकार्गो को मित्सुबिशी तनाबे फार्मा और टोबैको जायंट फिलिप मॉरिस का सपोर्ट मिला हुआ है।

4. नोवावैक्स (अमेरिका)

अमेरिका की ही कंपनी नोवावैक्स के वैक्सीन का इंतजार भी अमेरिका में बेसब्री से हो रहा है। कंपनी ने पुणे के सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का करार किया है।

5. अनहुई झिफेई लॉन्गकॉम बायोफार्म्सुयिटकल (चीन)

चोंगकिंग झिफेई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की एक यूनिट की ओर से विकसित वैक्सीन के ट्रायल्स की शुरुआत जून में ही हो गई थी। इस वैक्सीन को अनहुई झिफेई लॉन्गकॉम बायोफार्मास्युटिकल्स और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने बनाया है।

नोटः कंपनियों के वैक्सीन और उनके अपडेट्स डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर है।

Sinking deep: Water table at Ghaziabad falls 12m in 4 years

GHAZIABAD: The groundwater level in Ghaziabad has depleted by almost12 metres in the past four years and experts have warned that the district would "stare at a water scarcity" if measures are not taken to replenish the waterbodies immediately. Data sourced from the UP government says that groundwater in the district has been depleting at the rate of around 3m every year since 2016. Four of five blocks in Ghaziabad have been put under the "notified" category, which means that water here has been extracted at a much higher rate than it has been recharged. The extraction rate of Ghaziabad city itself is more than 260%. "Till last year, the annual groundwater depletion rate hovered

around1.5m. But it has almost doubled now. There are areas where the water table has plummeted to as low as 48m. If the slide continues at this rate, we would stare at a water scarcity in less than a decade," said Gemini Rao, a citybased hydrologist. Data provided by the UP groundwater department showed the pre-monsoon level in the district to be 18.7m in 2016. In the next four year, it has gone down to 30.6m, a drop of 12m. Noornagar in Sihani area has seen the sharpest fall — from 29.4m in 2016, it has dropped to 48.3m this year, a drop of 19m. It is followed by Vijay Nagar, which has registered a depletion of 8.5m during the same period. Officials said the water level was recorded digitally at 39 places, of which 10 spots were categorised as "dry". "A dry spot means either the apparatus used for recording groundwater level had malfunctioned or the water table is so low that the recorder cannot register the data. There are a dozen spots where the groundwater level has depleted by more than 5m," said Rahul Dev Sharma, an engineer with the groundwater department. Asked how alarming the situation was in Ghaziabad, Rao referred to a composite water management index report released by Niti Aayog in 2019. The report said that "21 Indian cities, including Ghaziabad, may run out of groundwater in a couple of years, affecting a population of 100 million people". "The latest data on groundwater is a pointer to this. Of five blocks here in Ghaziabad, four have exceeded the water extraction capacity. The use of groundwater has been 140.9% in Bhojpur, while it has been 132.9% in Loni. In Ghaziabad, it is an alarming 263.3%," Rao said. Reasons for the sharp decline in water table range from vanishing waterbodies to rampant illegal extraction for commercial, construction and industrial purposes. Rapid urbanisation has also been blamed for the situation.

Sweaters, shoes and shawls: How help is pouring in from all quarters

GHAZIABAD: Sweaters, blankets, shawls, shoes and even washing machines… help is pouring in from all quarters for the farmers protesting at UP Gate. At a time the mercury levels are competing with each other every night to take the plunge, businessmen, NGOs and even students have come forward with warm clothes and other such protective gear. These apart, about 350 water- and air-proof tents are being set up along the Ghaziabad-Delhi lanes of the Delhi-Meerut Expressway for the farmers to spend the chilly nights free of cost. All they would need is just a phone number and a photo ID card to get access to the tents. A small group of businessmen

from Udham Singh Nagar, who helped fund the tents, said they came up with the idea after learning that a number of farmers had not been allowed by police to bring along their belongings. The tents are equipped with phone chargers, mattresses and blankets and can withstand all types of weather. Not just locally, the farmers' groups have also been getting help from their NRI relatives and friends.

Child PGI to get new bio-safety lab for RT-PCR tests by end of March

NOIDA: The Super Specialty Paediatric Hospital and Post Graduate Teaching Institute (SSPHPGTI), Sector 30, also known as Child PGI, is all set to have a bio-safety level 3 (BSL-3) lab for RT-PCR testing by March next year. It will be the first such lab for the district even as GIMS too has applied for its sanction. The Uttar Pradesh government has sanctioned Rs 2.8 crore for the setting up of the lab, which will come up on a 1,200 sqft area on the ground floor of the institute, Child PGI chief medical superintendent Dr DK Singh said. He added that the lab will be functional by April and will begin with four-five technicians. The lab is in addition to the National Institute of Cancer Prevention

and Research (NICPR) lab in Sector 39 which is the first BSL-3 level lab in UP with a testing capacity of 6,000 samples per day. A BSL-3 lab can handle potentially infected samples in a bio-contained environment with minimal human intervention. It also has in-built UV light which filters high efficiency particulate matter for sanitisation. "It works in negative pressure, so that the infection does not spread to the surrounding environment," she said.

Rail minister seeks clarity on forest land rent from Uttar Pradesh chief minister

GNOIDA: Does the public services department need to pay lease rent for using forest land in Uttar Pradesh, railways minister Piyush Goyal has asked UP chief minister Yogi Adityanath in a letter on December 19, said officials on Saturday. The matter pertains to about 12 hectares of forest land in Gulistanpur reserve forest area, which will be used by the ministry of railways to build its flagship programme — a dedicated freight corridor of 1.6 km . The letter was sent so that clarity is sought on the matter before inauguration of the corridor on December 29, said sources in the district administration. The agency executing the project, Dedicated Freight Corridor Corporation. had asked the district forest officer to give them the land. After

getting permission from forest department officials in Lucknow, the land was diverted to the corporation. A total of 3,750 trees were felled due to the project. The corporation has paid over Rs 40 crore for the land, which passes through the core area. However, the forest department asked the corporation to pay Rs 4.2 crore per annum as lease rent for using the land. "The lease rent has been levied as per the guidelines of the state government as well as provisions provided under the Forest Conservation Act. The state government has framed the policy and there is little that can be done from our end," said the district forest officer PK Srivastava. Sources said the land has been handed over on a 99-year lease period to the corporation and 10% of the land cost has to be commanded as annual rent for the diversion. The corporation said lease rent cannot be levied since it is being given to one of the public service departments. Goyal said no other state in India has raised demand for lease rent for diversion of forest land for both western and eastern legs of the freight corridors. "We have asked UP government to consult with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and review the decision of imposing lease rent like other states," said a senior officer.

Woman jumps off Noida flyover

NOIDA: Four persons in the city have allegedly committed suicide in separate incidents in the past 24 hours, the police said on Saturday. Two of the deceased were co-workers, they added. On Saturday, a 30-year-old woman attempted suicide by jumping off the loop of an elevated road opposite Prakash Hospital in Sector 33 of the city. The sector 24 SHO, Prabhat Dixit, said her co-workers have told the police that the incident happened at 2 pm when she had come out with them during lunch break."They said she had tried to take the extreme step earlier as well. Her family said she was in a relationship with a man, who stays near her rented accommodation," he said.

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

डीएम – 2824416
आवास – 2820106
एडीएम (सिटी) – 2828411
एडीएम (प्रशासन) – 2827016
सिटी मजिस्ट्रेट – 2827365
आयकर विभाग– 2714144
पासपोर्ट कार्यालय– 2721779

पुलिस अधिकारी

एसएसपी –2820758,9643322900
पुलिस अधीक्षक नगर–2854015
पुलिसअधी. यातायात–2829520
सीओ प्रथम– 2733070
सीओ द्वितीय – 2791769
सीओ एलआईयू– 2700925
सीओ लोनी– 3125539

जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए – 2791114
जीडीए सचिव – 2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. – 2710754
सी.एम.एस. – 2730038
आपातकालीन – 2850124
कोलम्बिया एशिया –3989896
यशोदा अस्पताल–2750001–04
गणेश अस्पताल –4183900
संतोश अस्पताल –2741777
सर्वोदय अस्पताल –2701694
नरेन्द्र मोहन अस्पताल 2735253
जिला अस्पताल(एम्बुलेंस) 2730038
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

जीएम 2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम – 2734906
कोतवाली – 2732099
जिला कन्ट्रोल रूम –2766898

पुलिस स्टेशन

एसएचओ इंदिरापुरम– –9643322921
एसएचओ खोड़ा– –9643322922
एसएचओ–साहिबाबाद– – 9643322923
एसएचओ लिंक रोड– –9643322924
कोतवाली – 2732088
सिहानी गेट – 2791627
कविनगर – 2711843
विजयनगर – 2740797
इंदिरापुरम – 2902858
लोनी – 2600097
अग्निशमन विभाग –2732099 9818702101
रेलवे इन्कवायरी –131

नगर निगम

नगरायुक्त– 2790425,2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता – 2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर –2797840, 139
रिजर्वेशन – 8888
रोडवेज इन्कवायरी –2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
Phone No.: 0120-4561000

26-year-old woman jumps to death with infant daughter

GHAZIABAD: A 26-year-old woman held her two-year-old daughter in her arms and jumped from the 4th-floor corridor outside their flat in Shalimar Garden on Saturday evening. The child died on the spot while her mother, Preeti, succumbed to her injuries in hospital after an hour. Preeti's family has lodged a police complaint, accusing her husband, Amit, of pushing her and their daughter to death. They alleged that Amit, a constable with Delhi Police, had been harassing her for a few months over dowry. The couple lived on the 4th floor of Delhi 99, a highrise in Shalimar Garden. A resident of the housing society said he came to know about the incident from the

security guards. "I rushed to the tower where the couple lived and found the woman and her daughter lying face down. There was blood all over. We informed police and a team arrived in the society within 10 minutes," he added. Alok Dubey, the circle officer of Sahibabad area, said it was around 7pm that Preeti jumped along with the little girl. "The guards saw them first and informed her husband, Amit. They were rushed to a nearby hospital.

Florist beaten to death on busy Ghaziabad road

GHAZIABAD: A 20-year-old man was arrested on Monday for allegedly killing a person over a business rivalry. One more person is absconding. The arrested has been identified as Govind, a resident of Loni, who runs a flower shop outside Mahakal temple in DLF of Loni. Police said the deceased, Ajay (28), also started a flower shop there about six months ago. "This hit Govind's business due to which the two used to quarrel. The used to fight in the past too but it was usually settled by some devotees," said SP (rural) Iraj Raja. "Around 12pm on Monday when Govind didn't find more customers at his shop, he went to Ajay's shop and asked him to remove his shop from that place.

Bills will free farmers from middlemen: VK Singh

GHAZIABAD: The three farm bills will "revolutionise" the agriculture sector and free farmers from middlemen, Union minister and Ghaziabad's BJP MP Gen (retd) VK Singh said on Friday. The minister, who addressed a gathering at an event in Razapur block, also appealed to the protesting farmers to study the laws. "The law will free the farmers who are in the clutches of middlemen but the farmers are being misled by a few to serve their own ends," Singh said at a programme organised to celebrate former prime minister Atal Bihari Vajpayee's birth anniversary. Similar events were organised in Modinagar, Bhojpur, and Loni. According Singh, the Narendra Modi government is the first one

to do so much for farmers. "By 2022, it is the Modi government's resolve to double the income of farmers through a slew of measures that are being taken and will be taken in future. I want to appeal to the protesting farmers that they should study the farm laws and talk to the government in case of any doubts. They should give up opposing the laws and not play at the hands of a few who have their own axe to grind," he said.

Bulk waste generators in Sector 18 market fined Rs 2.25 lakh

NOIDA: The Noida Authority on Monday levied a fine of Rs 2.25 lakhs on bulk waste generators in Sector 18 for flouting Municipal Solid Waste (MSW) Rules 2016. Companies fined include Matrix Platform Pvt Ltd Rs 1lakh, McDonald Family Restaurant Rs 75,000, Domino's Pizza Jubilant Wood Works Rs 25,000 and Equitas Bank Rs 25,000. Following instructions from Noida Authority CEO , Indu Prakash OSD and Gaurav Bansal assistant project engineer public health department inspected Sector 18 market on where the said fines were levied for 8 boxes of banned single use plastic along with non-segregated mixed waste spilled on road in the case of Matrix Platform Pvt Ltd which is a food delivery restaurant.

GNIDA offers plots for schools, colleges & hospitals

GNOIDA: The city is likely to get more number of schools, colleges and hospitals soon. Over the past week, the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) has launched industrial and institutional schemes comprising 50 plots. Besides new industries and educational institutes, the plots will also be used for religious places and other institutional purposes. The industrial scheme comprises 21 plots in Ecotech 1. Officials said that the 29 institutional plots put on the block are situated in various sectors. "We have identified residential blocks where more educational institutes and healthcare facilities are needed. Vacant institutional plots have been identified in such locations

and introduced in the latest scheme," said Deep Chandra, additional CEO of the authority. While the two nursery school plots have been introduced in Sector 3 and ETA 2, four plots that will be used for higher secondary schools have been earmarked in Sector 3, Knowledge Park 5 and Sector 2. The plot for a new hospital has been proposed in Sector Omicron 1."In absence of a good school in the neighbourhood, we are forced to send our children to Sector 21 in Noida. We need good schools in Greater Noida's Bisrakh since a lot of highrises have come up," said Anju Saxena, a homemaker who lives in Ace City in Sector 1. Officials said that if nobody comes forward to open higher secondary schools, the four plots will be available for an engineering college or a higher education institute. A total of 2.31 lakh sqm (57 acres) is on offer and the size of the plots vary between 1,000 sqm and 40,470 sqm (10 acres). Meanwhile, 19 industrial plots measure 2,000 sqm while the other two measure 12 and 20 acres. The industrial allotments will be done with a condition that the units will be functional within two years.

Blasts in scrap godown kill labourer, injure another

GZB : A 30-year-old labourer was killed while another was injured after a fire broke out in a scrap godown at an unauthorised colony in Loni on Thursday. According to the police, the deceased has been identified as Pappu, a resident of Seelampur in Delhi. His cousin Gunga has suffered burn injuries. Both used to work at the scrap godown for the past eight years. The godown belongs to a Delhi resident, Hakikat. The incident took place on the ground floor of the two-storey building in Ganga Vihar colony where the godown was located. Two families used to live on rent on the first and second floor of the building. On spotting the flames, the residents rescued themselves and Gunga by using the terrace of the adjacent building, however, the labour received 40% burn injuries till then.

GMC to float bonds, hopes to raise Rs 150 crore

GHAZIABAD: The Uttar Pradesh government has given its nod for the Ghaziabad Municipal Corporation (GMC) to float municipal bonds. Following the footsteps of its Lucknow counterpart, the Ghaziabad civic body will float the bonds by February next year and hopes to raise Rs 150 crore. Municipal bonds are debt instruments, under which, the investor is paid back the fixed amount of principal with interest over a period decided by the municipal body. These bonds come with a tenure of five to seven years. The money raised is then used to fund development projects. The GMC will use to amount to set up infrastructure in Indirapuram for treatment and usage of STP water for industrial purposes.

Recently, Lucknow became the first city in the state and seventh in the country to raise money through this route. "Chief minister Yogi Adityanath, in the first week of December, visited Mumbai during the listing of municipal bonds of Lucknow Municipal Corporation in Bombay Stock Exchange where he had announced that municipal bonds for GMC will be listed very soon," said AK Mishra, accounts officer, GMC. "The GMC bonds will be listed at the Securities and Exchange Board of India (SEBI) following which we will issue them," added Mishra.

'Drunk' youth mows down 5-year-old in Noida

NOIDA: A five-year-old child was mowed down by a speeding car and his mother injured in Sector 122, the police said on Monday. The accused driver, Tushar Rawat, was under the influence of alcohol at that time, they said. The accident took place at 6 pm on Sunday when the victims were crossing Parthala road and the Swift VDI hit them near Amrapali Zodiac society. The child, Rishabh Anand, died on the spot while his mother was taken to Kailash Hospital in Sector 71. She is currently undergoing treatment. Phase III SHO Jitendra Dikhit said: "An FIR has been lodged in the case under IPC sections 304 a (death due to negligence), 279 (rash driving) and section 185 of the MV Act." Rawat from Sector 34 is a student.

DPR, financial estimates for Noida Film City likely by March 2021: Official

NOIDA: The detailed project report, including financial estimates, for setting up a film city near Noida in Uttar Pradesh is likely to be ready by March 2021, according to a senior official. A consultant was selected on December 14 for preparing the DPR of the film city and once the report is ready, it will be sent to the state government for its approval, Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) CEO Arun Vir Singh said. "Property consultant CBRE South Asia, which is a Fortune-500 company, has been given three months time for completing the detailed project report (DPR) for the film city. But efforts are on to have it prepared even before that," he said. "Once we get the DPR, it will be sent to

the state's cabinet ministers through Film Bandhu (the government's nodal agency for film production-related works) and the government will take a decision on the best plan suitable for the project. Accordingly, further work will be taken up," Singh said. He said financial planning is also part of the study and a strategy will be developed to decide if the film city will be made on public-private partnership (PPP) mode or in some other way.

महामाया स्टेडियम के पास 28 एकड़ में विकसित किया जाएगा पिकनिक स्पॉट

गाजियाबाद : प्रदूषण और भूजल की समस्या को कम करने के लिए शहर में राजनगर एक्सटेंशन स्थित सिटी फॉरेस्ट की तर्ज पर महामाया स्टेडियम के पास 28 एकड़ में जंगल विकसित करने की योजना बनाई गई है। जिसमें सघन पौधारोपण किया जाएगा, जंगल में एक झील भी बनाई जाएगी। पौधों की वजह से हरियाली बढ़ेगी और प्रदूषण का स्तर कम होगा। शहरवासियों को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगी, झील से भूजल स्तर बढ़ाने की तैयारी है। मुख्य तौर पर इसे पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा, जिसमें लोग घूमने–फिरने आएंगे। नगर निगम ने सिटी फॉरेस्ट की तर्ज पर जीडीए से महामाया स्टेडियम के पास जंगल विकसित कराने की तैयारी की थी लेकिन बोर्ड बैठक में पार्षदों ने इस कार्य को जीडीए से न करवाकर खुद नगर निगम द्वारा कराने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके बाद अब नगर निगम की ओर से जंगल विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे इस पिकनिक स्पॉट में न केवल गाजियाबाद बल्कि गाजियाबाद की सीमा से लगे गौतमबुद्धनगर के लोग भी घूमने फिरने के लिए आ सकेंगे। खासतौर पर लाइनपार, सिद्धार्थ विहार और प्रताप विहार के लोगों में इसे लेकर खुशी है। उनको घर के पास ही पिकनिक स्पॉट में घूमने–फिरने का मौका मिलेगा।

12 करोड होंगे खर्च

महामाया स्टेडियम के पास जंगल बनाने में नगर निगम द्वारा 12 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिसकी घोषणा 15वें वित्त आयोग की बैठक में जंगल के विस्तार के लिए महापौर आशा शर्मा द्वारा की गई है।

बढ़ गई ITR दाखिल करने की समयसीमा

नई दिल्ली : सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब वित्त वर्ष 2019–20 का इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी, 2021 हो गई है। यह पहले 31 दिसंबर, 2020 थी। इसके अलावा कंपनियों द्वारा वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 15 दिन आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है। सरकार ने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सालाना रिटर्न प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है। वे करदाता जिनके खातों का ऑडिट करवाने की आवश्यकता है, उनके लिए असेसमेंट ईयर 2020–21 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दी गई है।

मुआवजे के विवाद में प्रभावित हो रहा दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे का काम

गाजियाबाद : मुआवजे के विवाद और किसानों के आंदोलन की वजह से दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे का काम प्रभावित हो रहा है। मुआवजा नहीं दिए जाने की वजह से आए दिन किसान किसी न किसी एरिया में काम को रुकवा देते हैं। मंगलवार को डासना के पास आकाशनगर एरिया के प्रभावित लोगों ने एक्सप्रेसवे का काम रुकवा दिया। साथ ही भविष्य में यहां पर काम नहीं करने की चेतावनी भी दी। यूपी गेट के पास किसानों के आंदोलन की वजह से भी काम प्रभावित हो रहा है। निर्माण सामग्री के पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है, जबकि इस प्रॉजेक्ट की डेडलाइन 31 जनवरी 2021 तय की जा चुकी है। ऐसे में तय समय के भीतर प्रॉजेक्ट को पूरा करना एनएचएआई के अधिकारियों के लिए चुनौती है। आकाशनगर में करीब 250 की संख्या में घर बन चुके हैं, लेकिन इसी रास्ते से डीएमआई जाना था, इसलिए इन घरों को खाली कराकर तोड़ दिया गया। मास्टर मनोज नागर ने बताया कि इन लोगों को प्रशासन ने अभी तक केवल आश्वासन दिया है, लेकिन मुआवजा नहीं दिया है, जिससे लोग किराये के मकान में रहने को मजबूर हैं। महरौली के पास एनएचएआई को अभी तक 300 मीटर जमीन सड़क बनाने के लिए नहीं मिली है, जब भी यहां निर्माण कार्य शुरू होता है तो विवाद हो जाता है। मामला निपटाने की जिम्मेदार मंडलायुक्त ने जिला प्रशासन को सौंपी है।

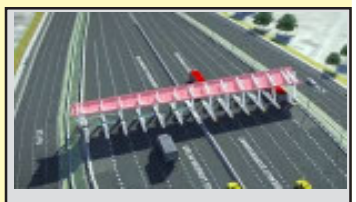

रेट को लेकर दिक्कत

डासना से मेरठ की तरफ से जाते हुए डीएमई के लिए कई गांव की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन इसमें मुरादाबाद, कलछीना समेत कई अन्य गांव हैं, जिन्हें मुआवजे का रेट अलग–अलग दिया है। इसका भी अभी तक विवाद चल रहा है।

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.L Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor : Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in **(RNI. No) : UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18.** Advertisement : Ph. No. : 0120-2850800, 2850297, Fax : 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.